महत्वपूर्ण एवं खास

एकलव्य विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण

कोरबा। नगर पंचायत छुरीकला मे संचालित एकलव्य सयुंक्त आवासीय विद्यालय मे जिला सहायक आयुक्त माया वारियर अपनी टीम के साथ पहुंचीं। उन्होंने छात्र छात्राओं से भेंट कर पढाई को लेकर चर्चा की। अगले माह से शुरू होने वाले 10 वी 12 वी सी बी एस ई बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला सहायक आयुक्त माया वारियर विघालय पहुंच कर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा ली। इस दौरान विद्यालय प्राचार्य ने परीक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी दी गई तथा सहायक आयुक्त विद्यालय के छात्र छात्राओं से भेंट कर विद्यालय की व्यवस्था व पढाई को लेकर सीधे बातचीत कर परीक्षा मे अच्छे अंक लाने कि टिप्स बतायी गई। शिक्षक शिक्षिकाओं से भी पढाई को लेकर चर्चा की गई। शिक्षकों को निदेशक दी गई 5 वर्ष के प्रश्न पत्र व माडल प्रश्न पत्र बनाकर अध्ययन करा कर तैयारी करायें। इस दौरान जिला सहायक आयुक्त का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया।

फरार आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। अवैध शराब के साथ एक स्थान पर मिले आरोपी को गिरफ्तार करने का काम कोरबी पुलिस ने किया है। मामला दर्ज किये जाने के बाद से वह फरार था। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट पेश किया था। कोरबी चौकी के एएसआई टोप्पो ने बताया कि कुम्हारी दर्री निवासी 50 वर्षीय सुकुल पंडो के विरूद्ध 34.36 आबकारी एक्ट का प्रकरण बीते वर्षों में कायम किया गया था। तभी से वह फरारी काट रहा था। लंबित मामलों का निकाल बाहर करने के लिए विशेष अभियान पुलिस चला रही है। इसी सिलसिले में यहां.वहां छापामारी का काम जारी है। एक सूचना पर पंडो को ठिकाने से गिरफ्तार किया गया।

बंद संयंत्र के अधिकारियों से मुलाकात

कोरबा। बिजली कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल के नेतृत्व में विद्युत मंडल के बंद पड़े संयंत्र के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस संयंत्र में150 कर्मचारी अभी भी कार्यरत है। संयंत्र के भीतर अभी भी कुछ विभागों में काम हो रहे है। काम में लगे कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। सुविधाओं में कटौती होने से कर्मचारी नाराज हो गये है। जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल में मुलाकात की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अब सुविधाओं में कटौती नही होगी।

कोयला खदान मजदूर संगठन की बैठक हुई

कोरबा। भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन के कार्यकाल दो वर्ष पूर्ण होने जा रहे है। हर दो साल के बाद सममेलन का आयोजन कर नये कार्यकारिणी तैयार की जाती है जिसको लेकर गेवरा युनियन कार्यालय में बैठक हुई। पदाधिकारियों ने यहां पर एजेंडा के बिंदुओं के संबंध में बातचीत की। अगला सममेलन मार्च माह में होगा जिसकी तैयारी अभी से की जायेगीं। इस बैठक में लक्ष्मण चंद्रा, टिकेश्वर राठौर, अशोक सर्यवंशी,अ श्विनी मिश्रा, के.पी.पाटले, प्रीतम लाल, बाबूलाल चन्द्रा, दादूराम राठौर, राजेन्द्र यादव सहित अनेको कार्यकर्ता मौजूद थे।

करतला रेंज में एक दंतैल हाथी फिर आया

कोरबा। वनमंडल कोरबा के करतला रेंज में एक दंतैल हाथी फिर आ गया है। पड़ोसी रायगढ़ जिले के छाल परिक्षेत्र से अचानक पहुंचे दंतैल को आज सुबह रेंज अंतर्गत तुर्रीकटरा व कोटमेर जंगल में विचरण करते हुए देखा गया और इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचकर दंतैल की निगरानी में जुट गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी के दस्तक देते ही विभाग सतर्क हो गया है। क्षेत्र में हाथी के आगमन की मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि दंतैल कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए वे सावधानी बरतें तथा दंतैल की मौजूदगी वाले जंगल से दूरी बनाए रखें।

उच्च शिक्षामंत्री पटेल ने 1 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन

ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बन रही है शासन की योजनाएं-उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल

रायगढ़। उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल आज खरसिया विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में 1 करोड़ 25 लाख 25 हजार रुपये के कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया।

उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने इस दौरान ग्रामवासियों को संबोधित करते हुये कहा कि सरकार निरंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाओं का प्राथमिकता से निर्माण कर क्रियान्वयन कर रही है। शासन गाँव में रहने वाले लोगों को उनकी जरुरत के अनुसार आजीविका के साधन मुहैय्या कराने के साथ ही उनकी आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न नीतियां बनायी है तथा योजनायें शुरू की हैं। किसान, श्रमिक, आदिवासी परिवारों तक सबके विकास को ध्यान में रख कार्य किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से धान सहित अन्य फसलों की अधिक कीमत मिली। आदिवासी अंचलों के निवासियों के आजीविका का मुख्य स्त्रोत वनोपज के भी समर्थन मूल्य में खरीदी के दायरे को विस्तार देकर समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी। जिसका लाभ वनवासी परिवारों को मिल रहा है। शासन जहां एक ओर किसानों के लिए योजनाएं चला रही है वहीं गांवों में निवास करने वाले भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी योजना शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए घर-घर तक नल कनेक्शन विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कुपोषण मुक्ति की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।

इस मौके पर सभापति जिला पंचायत संतोषी राठिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत खरसिया मेहत्तर उरांव, सदस्य जनपद पंचायत प्रीतम राठिया, सरपंच पुछियापाली ललिता राठिया, सरपंच बर्रा उमा राठिया, सरपंच काफरमार शकुंतला राठिया, रामदयाल राठिया, अभय महंती, मनोज गबेल, नेत्रानंद पटेल, सुलोचना सिदार, बीडीसी ईश्वरी राठिया, पवन कुमार राठिया सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण व भूमिपूजन- उच्च शिक्षामंत्री पटेल ने 1 करोड़ 25 लाख 25 हजार रुपये के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें ग्राम-टांडापारा ग्राम पंचायत पुछियापाली में 3 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, 10 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण एवं 01 लाख 20 हजार रुपये की लागत से पचरी निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह ग्राम पंचायत गांड़ापाली में 6 लाख 50 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण साजापाली, ग्राम पंचायत बर्रा में 5 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण, 6 लाख 45 हजार रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण, 2 लाख रुपये की लागत से स्वागत गेट निर्माण, 2 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक मंच निर्माण, 2 लाख 20 हजार रुपये की लागत से बीच बस्ती में छज्जा निर्माण, 01 लाख 40 हजार रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य, 2 लाख रुपये की लागत से अहाता निर्माण कार्य प्रा.शा.रावनभांठा, 01 लाख 20 हजार रुपये की लागत से ऊपर तालाब में पचरी निर्माण कार्य, 10 लाख रुपये की लागत से आदिवासी भवन निर्माण, 15 लाख 22 हजार रुपये की लागत से आयुर्वेदिक भवन, 14 लाख 88 हजार रुपये की लागत से सिदार मोहल्ला में सीसी रोड निर्माण, 14 लाख 88 हजार रुपये की लागत से चमकट्टा पारा में सीसी रोड निर्माण एवं 10 लाख रुपये की लागत से आदिवासी भवन निर्माण, ग्राम पंचायत खम्हार में 5 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य, 2 लाख रुपये की लागत से ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र, 01 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य कोठीकुण्डा तथा कोठीकुण्डा में 6 लाख 45 हजार रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं 13 लाख 39 लाख रुपये की लागत से खम्हार में उप स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण कार्य शामिल है।

खुलने से पहले दम तोड़ा श्रम कार्यालय का दाल-भात केंद्र, संचालन की दिशा में पहल नहीं

कोरबा। जिला श्रम कार्यालय में पहुंचने वाले श्रमिकों को रियायत दर में भोजन देने के लिए बना दालभात केंद्र भवन खुलने से पहले खंडहर में तब्दील हो गया। निजी काम के लिए कार्यालय आने वालों को भोजन तो क्या पानी भी नसीब नहीं हो रहा। संचालन की दिशा में श्रम विभाग की ओर से पहल नहीं करने के कारण 23 लाख की लागत से बना भवन सात साल बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी रह गया।

श्रमिक हित में दाल भात केंद्र संचालन प्रत्येक श्रम कार्यालयों में किया जाना है। इस प्राविधान के अनुसार जिला श्रम कार्यालय में दाल. भात केंद्र निर्माण के लिए श्रम कल्याण मद से 2012 में 23 लाख की स्वीकृति मिली थी। भवन का निर्माण 2015 में पूर्ण हो गया। नियम के अनुसार निर्माण के बाद से ही संचालन शुरू हो जाना थाए लेकिन विभाग के अधिकारियों की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण भवन का उपयोग अब तक नहीं हो सका। भवन निर्माण का उद्देश्य केवल रियायत दर में श्रमिकों को भोजन प्रदान करना ही नहीं उनके विश्राम की सुविधा भी देना है। निर्मित भवन में श्रमिकों के ठहरने की भी व्यवस्था है। श्रमिक हित में उपयोग में नहीं लाए जाने के कारण यहां श्रम कार्यालयों की स्टेशनरी, टूटी कुर्सियां, श्रमिकों को वितरित किए जाने वाला सामान व कबाड़ रखा है। विभाग में अधिकारियों की बदलियां होती रही लेकिन किसी ने भी आज तक संचालन के संबंध में जागरूकता नहीं दिखाई। दाल-भात केंद्र का निर्माण औद्योगिक संस्थानों के आसपास करने का नियम है। तत्कालीन अधिकारियों ने नियम को ताक में रख सरकारी धन का दुरूपयोग करते हुए तंग जगह में भवन का निर्माण कर दिया है।

दाल-भात केंद्र संचालन के लिए भवन का अधिक महत्व ऐसे जगह में आवश्यक होती है, जहां दिहाड़ी मजदूरी में जाने के लिए मजदूर सुबह एकत्र होते हैं। शहर के पुराना बस स्टैंड, रेलवे फाटक के पास मजदूर प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी पर जाने के एकत्र होते हैं। मजदूरों की सुविधा के लिए ऐसे ही जगह में केंद्र को खोला जाना था। श्रमिक एकत्र स्थल में दाल भात केंद्र नहीं होने के कारण कई श्रमिकों को भूखे पेटे ही काम पर जाना पड़ता है। जिले में राज्य शासन के अनुदान से कलेक्ट्रेट परिसर अन्नापूर्णा दाल.भात सेंटर का संचालन हो रहा था। जहां दस रूपये में भरपेट भोजन दिया जाता था। निजी संस्थानों को संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से रियायत दर में केवल चावल ही दिया जा रहा था। सामानों की कीमत बढऩे और कोरोना काल में कार्यालय बंद होने के कारण इस केंद्र का संचालन भी बंद हो गया।

पोषण पुनर्वास केंद्र में अव्यवस्था

कोरबा। कुपोषण की काली छाया के शिकार बच्चों को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जिला अस्पताल कोरबा में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित किया जा रहा है। इससे जुड़ी कई परेशानियां मरीजों और उनके परिजनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। इस कड़ी में आगामी दिनों में सुधारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर सुपोषण के क्षेत्र में काम करना तय किया है। लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सभी क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं। कोरबा के जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में वर्तमान में ऐसे बच्चों को रखा गया है जो कुपोषण का शिकार हैं और उन्हें बेहतर स्थिति में लाए जाने के लिए पूरक पोषण आहार के अलावा उपचार भी दिया जाना जरूरी है। तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों की शिकायत है कि यहां पर आलू और बड़ी से काम चलाया जा रहा है।

पोषण पुनर्वास केंद्र से लगकर सर्जिकल वार्ड स्थापित किया गया है इसके चलते स्थिति जटिल हो गई है और मरीजों के साथ समस्याएं पेश आ रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने आगामी दिनों में वार्ड की व्यवस्था को बदलने का मन बनाया है। बताया गया कि काफी समय से ट्रामा यूनिट रिक्त पड़ी हुई है इसलिए कुछ वार्ड को इसमें शिफ्ट कर सकते हैं।

कटघोरा पुलिस की कोशिश से युवती की जान बची

कोरबा। कटघोरा क्षेत्र में पुलिस की कोशिश के कारण एक युवती को बचा लिया गया। वह जेजरा बायपास पर बुरी तरह से छटपटा रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आनन-फानन में अस्पताल भिजवाने और वहां उपचार मिलने से युवती की सांसें लौटाई जा सकी।

कटघोरा थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी से बायपास पहुंच मार्ग पर मंगलवार की शाम एक युवती छटपटा रही थी। उसकी स्थिति देखकर लगा कि उसने जहर का सेवन किया है और रसायनिक प्रभाव से वह बुरी तरह से परेशान है। यह नजारा देख मौके पर से गुजर रहे लोगों ने कॉल कर कटघोरा पुलिस व डायल-112 को

सूचना दी। सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन व प्रधान आरक्षक संदीप पांडेय तथा डायल 112 की टीम मौके पर एक साथ पहुंचे। जहर के नशे में छटपटा रही बेहोश युवती को तत्काल कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहर के असर से बेहोश युवती को तत्काल सहायता मिलने से उसकी जान बच गई। कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन ने युवती के पास मोबाइल देखा और उस मोबाइल के जरिये प्रधान आरक्षक संदीप पांडेय द्वारा पतासाजी कर उसकी पहचान पोंडी उपरोड़ा निवासी के रूप में कई। खबर के अनुसार अफेयर्स को लेकर हुए विवाद पर उसने जहर खाकर खुदकुशी करने का प्रयास। कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य

केंद्र में जहां युवती का उपचार जारी है और स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि युवती की स्थति समान्य नही हो पाने के कारण अभी युवती का बयानऔर घटना का कारण सामने नही आ पाया है।

उपभोक्तओं दी जा रही थी कम सिलेंडर, खाद्य विभाग ने जब्त किये 294 सिलेंडर

कोरबा। शहर के मानिकपुर स्थित भारत गैस एजेंसी से जिला खाद्य विभाग ने 294 गैस सिलेंडर जब्त किया है। डिलिवरी के दौरान उपभोक्तओं को कम तौल के सिलेंडर देने की शिकायत पर विभाग ने कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण नहीं करने के कारण एजेंसी संचालकों में बिना तौल के सिलेंडर देने का मनोबल बढ़ गया है। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद अब विभाग में जागरूकत आई है।

गैसे सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर दोहरा खेल चल रहा है। उपभोक्ताओं को सुविधा का सब्जबाग दिखाकर बिना तौले सिलेंडर दिया जा रहा है। नियमानुसार डिलीवरी समय वाहन तौल यंत्र का होना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता द्वारा तौल की मांग किए जाने उन्हे संतुष्ट किया जा सके। जिले भर में अलग-अगल स्थानों में 20 से भी अधिक गैस एजेसिंया संचालित हैं। कम तौल की जानकारी होने के बावजूद खाद्य विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती। विभाग द्वारा सक्रियता के साथ कार्रवाई की जाती तो उपभोक्ताओं को शिकायत की नौबत नहीं आती। यहां बताना होगा कि कम तौल के गैस डिलिवरी के लिए जिल भर में गिरोह का काम कर रहे हैं। भारत गैस एजेंसी से जब्त किए किए गए सिलेंडर में दो से ढाई किलो की कमी पाई गई है। एजेंसी में तौल यंत्र नहीं रखा जाता है। सिलेंडर लिए पहुंचने वाले उपभोक्ताओं की ओर से तौल की मांग किए जाने पर यंत्र को सुधार के लिए देने का बहाना बना कर टाल दिया जाता है। डिलीवरी के लिए पहुंचने के दौरान भी यही बहाना बनाया जाता है। शहर के बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से कम तौल की अधिक ठगी की जा रही।

घर पहुंच गैस सिलेंडर सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को तौल के साथ सिलेंडर पाने का अधिकार है। इसी तरह प्लांट से सिलेंडर लोड करने के पहले तौलने का निमय है। इसी तरह गोदाम में उतारे जाने के दौरान भी तौल का प्रावधान है। सिलेंडर का वजन कराने में अक्सर लोग संकोच करते हैं। इसी का लाभ उठाकर डिलीवरी करने वाले कम तौल का सिलेंडर थमाने में पीछे नहीं रहते।

दुकान किराया बकायादारों पर निगम की कार्यवाही जारी

निगम ने पुन: 07 दुकानों, 04 ठेलों पर लगाया ताला

कोरबा। दुकान किराये की बकाया राशि संबंधित दुकानदारों द्वारा निगम कोष में जमा न करने के परिणाम स्वरूप आज नगर पालिक निगम केारबा द्वारा पुन: 07 दुकानों एवं 04 ठेलों पर ताला लगाया गया, वहीं अब तक 85 दुकानों पर ताला निगम द्वारा लगाया जा चुका है। इसी प्रकार दुकान किराये की बकाया राशि के रूप में 93 लाख रूपये से अधिक की वसूली भी दुकानों में पहुंचकर निगम के राजस्व अमले के द्वारा की जा चुकी है। जिन दुकानों पर ताला लगाया गया है, उनसे संबंधित दुकानदारों को राजस्व अमले ने कड़ी हिदायत भी दी कि वे बकाया राशि जमा कराएं तभी उनके दुकानों का ताला खोला जाएगा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में निर्मित दुकानों, भवनों आदि को लीज किराये पर आबंटित किया गया है। इन दुकान संचालकों द्वारा बरसों से किराये की राशि निगम कोष में जमा नहीं कराई जा रही थी, निगम द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया राशि की अदायगी नहीं की गई तथा एक बड़ी राशि दुकान किराये के रूप में निगम को प्राप्त करनी शेष थी। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के राजस्व अमले द्वारा दुकान किराये के बकायादारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इन बकायादारों पर कार्यवाही करते हुए पुन: 07 दुकानों व 04 ठेलों पर ताला लगाया गया, जिनमें जिला चिकित्सालय स्थित छोटी दुकान क्र. 02, 03, 04, 05, बड़ी दुकान क्र. 03 तथा महाराणा प्रताप नगर स्थित दुकान क्र. 01, 04, 12 तथा निगम के ठेला क्र. 12, 15, 19, 43 में ताला बंदी की गई, वहीं अब तक निगम द्वारा 85 दुकानों में ताला लगाया जा चुका है, इसके साथ ही दुकान किराये की बकाया राशि के रूप में 93 लाख रूपये से अधिक की वसूली भी की गई है।

बकाया राशि जमा करें, असुविधा से बचें- आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के करदाताओं एवं दुकान भवन किराया के बकायादारों से कहा है कि वे बकाया कर एवं निगम को देय भवन, दुकान किराया की राशि समय पर निगम कोष जमा कराएं। उन्होने आगे कहा है कि करों से प्राप्त राशि के माध्यम से ही निगम द्वारा विभिन्न मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाती है तथा नगर विकास के कार्य किए जाते हैं, निगम को समय पर करों का भुगतान न मिलने से नागरिक सुविधाएं व नगर विकास के कार्य प्रभावित होते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सरकारी अस्पताल से मरीजों का रेफरल रोकने रखी जाए कड़ी निगरानी: कलेक्टर

- बच्चों के आवासीय संस्थाओं के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की लगेगी ड्यूटी
- सी-मार्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार
- कलेक्टर रानू साहू ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

कोरबा। मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल से मरीजों का अनावश्यक रेफरल रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मरीजों के रेफरल रोकने आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने मरीजों के अनावश्यक रेफरल रोकने के दिए निगरानी टीम गठित करने और अस्पताल के प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में कलेक्टर साहू ने जिले के सभी अस्पतालों के अस्थायी, स्थायी लाइसेंसों की जानकारी देने के निर्देश सीएमएचओ डॉ.बी.बी. बोडे को दिए है। उन्होंने अस्पतालों के संचालन के लिए नर्सिंग होम एक्ट के तहत जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की भी जानकारी देने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। बैठक में एडीएम सुनील नायक, जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे, संयुक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर साहू ने स्थानीय उत्पादों को शापिंग मॉल की तर्ज पर बाजार उपलब्ध कराने विकसित किए जा रहे सी-मार्ट की भी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने सी-मार्ट में महिला समूह द्वारा उत्पादित सामानों और स्थानीय उत्पादों को ब्रिकी के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बच्चों के आवासीय संस्थाओं की निरीक्षण के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य जांच और ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराने स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मरम्मत लायक स्कूलों की जानकारी देने के निर्देश सभी जनपद पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर साहू ने राशन दुकानों का निरीक्षण कर लोगों को दिए जा रहे राशन सामग्रियों की क्वालिटी का भी निरीक्षण करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए। कलेक्टर ने बैठक में मिलेट मिशन के अंतर्गत जिले में कोदो-कुटकी एवं रागी फसलों के उत्पादन बढ़ाने कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश कृषि अधिकारियों को दिए।